समुदाय व संरक्षण

समुदाय आधारित जैवविविधता संरक्षण तथा आजीविका सुरक्षा

अंक ९, नं. ४ जूलै २०१९ - दिसंबर २०१९

विषय सूंची

प्रस्तावना

१. समाचार और जानकारी
- खाद्य सुरक्षा को बेहतर करने के लिए प्रमुख कदम
- कोरोनावायरस खतरे के समय में भारत को चीन से कृषि, खाद्यान्न और समुद्री आयात के क्षेत्र में बहुत सावाान रहना होगा : व्यापार विशेषज्ञ

२. दृष्टिकोण
- पोषण और खाद्य सुरक्षा
- उधार लो, बचाओ, आपस में बांटों: ३ तरीके जिससे हमारी खाद्य प्रणाली लोकतांत्रिक बन सकती है

३. आयोजन
- मोबाइल जैवविविाता उत्सव ... दलित औरतों का २० वर्षो से चला आ रहा उत्कृष्ट प्रयास

४. आशा के संकेत
- कच्छ के वागड़ या काला कपास : (लगभग) मौत से वापस

५. अंतर्राष्ट्रीय
- शहर और देश के बीच: घरेलू कामगार खाद्य संप्रभुता का निर्माण कर रहे हैं

प्रस्तावना

भारतीय कृषि क्षेत्र विभिन्न चुनौतियों से घिरा हुआ है। इनमें शामिल हैं आपूर्ति में बाधाएं, पानी की कमी, छोटे खेत, प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद का कम होना और अपर्याप्त सिंचाई, शोा एवं विकास पर तथा प्रोटीन गुणवत्ता पर सार्वजनिक खर्च में कमी। स्वभाविक रूप से इससे खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पैदा होते हैं। यह कहना स्वयं सिद्ध सत्य होगा कि वर्तमान में कृषि कार्यक्षेत्र जिस संकट से गुज़र रहा है, उसकी शुरुआत नब्भे के दशक की शुरुआत में हो गई थी, जब भारत ने नव–उदारवादी बनने का निर्णय लिया था। उसके बाद से लगभग तीन दशकों में इसके जो निरंतर भयानक रूप सामने आए हैं उनमें कृषि संकट और किसानों की आत्महत्याएं शामिल हैं – अभी तक के अनुमानों के अनुसार, कुछ गिने–चुने लोगों के मुनाफे और प्राकृतिक संसाधनों के साथ–साथ ज़्यादातर लोगों को चूस लेने वाली विकास की रूपरेखा पर आधारित कृषि नीतियां लगभग २.५ से ३ लाख लोगों को शिकार बना चुकी हैं। इसके अलावा, कीटनाशकों, कृत्रिम उर्वरक आदि के उपयोग से ज़मीन को हुई क्षति का तो इस सच्चाई–पर्यन्त निंदात्मक समय में वर्णन भी नहीं किया जा सकता।

यह पूरे विश्व भर का सत्य है। लगभग एक दशक पहले, दि साईंटिफिक अमेरिकन में एक लेख छपा जिसका शीर्षक था ''कुड फूड स्टोरेज ब्रिंग डाउन सिविलाइज़ेशन। कुछ दशकों पहले लोग ऐसे सुझाव का मज़ाक उड़ाते, लेकिन अब जलवायु संकट के समय में नहीं। उसी समय, भूमण्डलीय दक्षिण के कई देशों में खाद्यान्न से जुड़े दंगे फैले क्योंकि लोग तेज़ी से सिकुड़ती आपूर्ति में से कुछ अंश खाद्य पदार्थ प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। विश्व भर में, लगभग एक अरब लोग स्थायी और गंभीर रूप से भुखमरी का सामना कर रहे हैं, जबकि दो अरब से अिक लोग हमेशा खाद्य असुरक्षा की स्थिति में रहते हैं – जो कुछ समय ही भोजन जुटा पाते हैं और उन्हें यह भी नहीं पता होता कि अगला भोजन कहां से आएगा। दूसरी ओर टी.वी. चैनलों पर बहुसांस्कृतिक भोजन के आकर्षण को दर्शाने वाले भोजन के कार्यक्रम दिखाए जाते हैं, जिन्हें इस दुनिया के कुछ अल्पसंख्यक लोग ही प्राप्त करने में समर्थ हैं।

यह मुद्दा एक ढांचागत समस्या है। जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था काम करती है – पूंजिवाद के भक्षक प्रारूप पर आधारित, वह मुनाफे की खोज के निम्नलिखित परिणाम सुनिश्चित करता है :

- पूंजिवादी कृषि के फैलाव के कारण मी के पोषक तत्वों का विघटन
- रसायनिक और जीवश्म ईंन पर आधारित गहन कृषि पतियों के कारण पारिस्थितिकीय विनाश
- आनुवांशिक रूप से संशोाित बीजों की बढ़ती भूमिका के चलते कृषि पतियों में कारपोरेट नियंत्रण का समेकन
- कृषि व्यापार में किसानों का मज़दूर बनना
- किसानों का भारी संख्या में शहरी झुग्गियों में पलायन, जहां वैसे ही नौकरियों की कमी है।

इस सबके कारण कई पारिस्थितिकीय आपदाएं पैदा हुई हैं। इनमें शामिल हैं, नाइट्रेट्स, फोसफेट्स, कीटनाशकों से भूमिगत और सतही जल का प्रदूषण; फसल पैदा करने वाले खेतों में पोशक तत्वों की कमी आना आदि।

तो फिर क्या किया जाए? लोग व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर अपने–अपने तरीकों से इस स्थिति का सामना कर रहे हैं – नई प्रकार की कृषि पतियां, जैसे कि एग्रोइकॉलजी, पर्माकल्चर आदि अपना कर, जो कि पारिस्थितिकीय तन्यकता, सामाजिक न्याय, स्थानीयकरण आदि के मूल्यों पर आधारित हैं। वे सहकारी संघ बना रहे हैं, भूली हुई पारंपरिक प्रणालियों को फिर से शुरु कर रहे हैं, जैसे कि बीज बैंक, बीज जैवविविाता आदि। पीपल इन कन्ज़र्वेशन का यह अंक ऐसे ही लोगों को समर्पित है।

मिलिंद

१. समाचार और जानकारी

खाद्य सुरक्षा को बेहतर करने के लिए प्रमुख कदम

भारत को अपनी खाद्य सुरक्षा बेहतर करने के लिए बड़े कदम उठाने होंगे क्योंकि उसके सामने आपूर्ति बाधाएं, पानी की कमी, छोटे खेत, घरेलू उत्पाद कम होने और अपर्याप्त सिंचाई जैसी समस्याएं खड़ी हैं – ऐसा आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया।

उसमें कहा गया – कृषि उत्पाद में बढ़ोतरी के साथ–साथ, उससे जुड़े कार्यक्षेत्रों जैसे कि दुग उत्पादन, मुर्गी पालन, मछली पकड़ने और मवेशी पालन को भी बढ़ावा देने की ज़रूरत है, जो कि ग्रामीण समृद्धि में बढ़ोतरी के सरकारी उेश्य को प्राप्त करने में मदद करेगा।

पिछले वर्ष, भूमण्डलीय खाद्य सुरक्षा अनुक्रमणिका में आंके गए ११३ देशों में से भारत का स्थान ७६ रहा। इसे चार पैमानों पर आंका गया था – सामर्थ्य, उपलबता, गुणवत्ता, सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधन। इसमें कहा गया, ''भारत की खाद्य सुरक्षा को सबसे बड़ी चुनौती का सामना प्रति व्यक्ति कम घरेलु उत्पाद, पर्याप्त आपूर्ति, शोध और विकास पर सार्वजनिक खर्च तथा प्रोटीन की गुणवत्ता के क्षेत्रों में करना है।

सर्वेक्षण में कहा गया कि भारत को केवल खाद्य सुरक्षा ही नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत, जहां ज़्यादातर लोग रहते हैं, के कल्याण के लिए भी इन मुद्दों को संबोधित करना ज़रूरी है।

किसानों को मौसम की वास्तविक समय पर आधारित जानकारी और निवेश तथा उत्पाद की कीमतों की जानकारी की आवश्यकता है जिससे कि वे अपना उत्पादन और समृद्धि बढ़ा सकें – इसमें कहा गया है।

यह भी कहा गया कि मोबाइल फोन के मायम से किसानों को उपयोगी जानकारी पहले ही प्राप्त होने लगी है। ''खराब बुनियादी ढांचे के संदर्भ में, कृषि में आई.सी.टी. अपनाने से बाज़ारों तक पहुंच में बढ़ोतरी, आर्थिक समावेश को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही जल्दी चेतावनियां देने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा, जो कि छोटे किसानों के विकास के लिए अत्यंत ज़रूरी है।''

सर्वेक्षण में कहा गया है कि पानी और उर्वरकों का कुशल उपयोग बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई मौजूदा प्रणालियां और परियोजनाएं पानी की कमी और पोशक तत्वों के गलत इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही हैं।

स्रोत: <https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/indicators/major-steps-needed-to-improve-food-security/articleshow/70082108.cms?from=mdr>

कोरोना वायरस खतरे के समय में भारत को चीन से कृषि, खाद्यान्न और समुद्री आयात के क्षेत्र में बहुत सावाान रहना होगा : व्यापार विशेषज्ञ

व्यापार विशेषज्ञों का कहना है कि चीन में कोरोना वायरस के फैलाव के कारण, भारत को अपने बंदरगाहों पर चीन से आयात होने वाले कृषि उत्पाद, खाद्यान्न और समुद्री उत्पादों के क्षेत्र में बहुत सावाान रहना होगा।

विशेषज्ञों ने कहा है कि बंदरगाह प्राधिकरणों को (जानवरों से जुड़े) स्वच्छता मानकों का सही तरीके से पालन करना चाहिए।

''क्योंकि यह घातक कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, भारत को चीन से कृषि, खाद्य और समुद्री उत्पाद आयात करते समय सावधान रहना चाहिए, राकेश मोहन जोशी, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड।

इसी प्रकार के अपने विचारों को साझा करते हुए जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बिस्वजीत ार ने कहा कि वायरस के प्रसार के कारण, बंदरगाहों पर बुनियादी ढांचे को बेहतर करने का यह अच्छा मौका है।

उन्होंने कहा, ''स्वच्छता मानकों का उचित रूप से पालन और प्रबांन किया जाना चाहिए।

साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इसका कोई प्रमाण नहीं है कि यह वायरस केवल गैर–जीवित चीज़ों के मायम से ही फैल रहा है, लेकिन ''हमें कोई खतरा नहीं लेना चाहिए।

ार ने कहा कि सरकार को बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों को सुरक्षात्मक कपड़े और मास्क उपलब कराने चाहिए, खासकर उन कर्मचारियों को जो चीन से आने वाले कृषि, खाद्य एवं समुद्री पदार्थो के माल से संबंाित काम करते हैं।

उन्होंने जोड़ा, ''यह हमारे लिए मौका है कि हम बंदरगाहों पर स्वच्छता मानकों से जुड़े बुनियादी ढांचे को बेहतर करें।

चीन भारत का एक प्रमुख व्यापार सहभागी है। भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार २०१७–१८ में ८९.७१ अरब डॉलर से गिरकर २०१८–१९ में ८७ अरब डॉलर रह गया।

जहां भारत का निर्यात २०१८–१९ में केवल १६.७५ अरब डॉलर था, वहां आयात कुल ७०.३१ अरब डॉलर रहा। २०१८–१९ में दोनों

देशों के बीच व्यापार घाटे की राशि ५३.५७ अरब डॉलर रही। भारत इस बढ़ते घाटे को कम करने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है। जब पूछा गया कि क्या भारत को इन चीज़ों के चीन से आयात पर रोक लगानी चाहिए, तो एक विशेषज्ञ का कहना था कि यह ''अच्छा उपाय नहीं है, बल्कि ''हमें स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षात्मक उपाय करने चाहिए और सरकारी विभागों को कोई भी कदम उठाने से पहले वाणिज्य मंत्रालय से विमर्श करना चाहिए।

चीन ने उम्मीद व्यक्त की है कि भारत उस पर व्यापारिक बाधाएं लागू नहीं करेगा और हुबेई प्रांत में कोरोना वायरस महामारी के कारण लोगों को चीन जाने से नहीं रोकेगा।

चीन में वायरस से होने वाली मृत्यु की संख्या ४९० तक पहुंच चुकी है, और कोरोना वायरस से ग्रस्त लोगों की संख्या २४,३०० है।

विश्व स्वास्थ्य संस्थान ने विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना वायरस के मामले पाए जाने पर इसे भूमण्डलीय स्वास्थ्य आपातकालीन स्थिति घोषित कर दिया है।

स्रोत: <https://www.news18.com/news/business/india-must-be-cautious-about-agri-food-and-marine-imports-from-china-amid-coronavirus-scare-trade-experts-2489021.html>

✦✦

२. दृष्टिकोण

पोषण और खाद्य सुरक्षा

चुनौती

लगभग १९.५ करोड़ कुपोषित लोगों की संख्या के साथ, भारत में वैश्विक भुखमरी का एक-चौथाई भार मौजूद है। भारत में, लगभग ४.७ करोड़, या १० में से ४ बच्चे अपनी संपूर्ण मानवीय संभावनाओं को पूरा नहीं कर पाते क्योंकि वे जीर्ण कुपोषण से ग्रस्त या अविकसित हैं। अविकसित होने के कई प्रभाव हैं, जैसे कि सीखने की क्षमता में कमी, स्कूल में खराब प्रदर्शन, आमदनी में कमी और जीर्ण बीमारियों का बढ़ा हुआ खतरा। यह प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर भी असर डालते हैं क्योंकि कुपोषित लड़कियां और औरतें अक्सर जन्म पर कम वज़न वाले शिषुओं को जन्म देती हैं। भारत में अकि वज़न और मोटे बच्चों और किशोरों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है, जिसके जीवन भर रहने वाले परिणाम होते हैं, जैसे कि वयस्कता में गैर-संचारी रोगों से ग्रस्त हो जाना।

सरकार ने विशाल स्तर पर खाद्य सुरक्षा और गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रम चलाए हैं लेकिन उनमें लोगों को शामिल करने या बाहर रखे जाने के स्तर पर कई कमियां हैं। औरतें और लड़कियां विशेष रूप से वंचित हैं। हांलाकि देश ने खाद्य आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली है, नई चुनौतियां सामने आ खड़ी हुई हैं : कृषि की बढ़ोतरी में गिरावट, जलवायु परिवर्तन, ज़मीनों की गुणवत्ता में गिरावट और सिकुड़ती जैव-विविता। भारत में, असंतुलित उर्वरक उपयोग और यूरिया के अत्यकि इस्तेमाल के कारण, विशाल स्तर पर कृषि भूमि बंजर होती जा रही है।

भारतीय सरकार की परियोजनाएं व प्रयास

१९५०-५१ में २.५ करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन से २०१४-१५ में ५ करोड़ टन के पांच गुणा बढ़े खाद्यान्न उत्पादन के साथ, भारत खाद्य सहायता पर निर्भर होने से हटकर खाद्य निर्याता बन गया। वर्ष २०१६ में, सरकार ने कई परियोजनाएं चलाईं जिससे २०२२ तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाए। इन परियोजनाओं का लक्ष्य है कि वे कृषि उत्पादन बढ़ाने में आने वाली अड़चनों को दूर करें, विशेषकर वर्षा पर आधारित क्षेत्रों में। इन परियोजनाओं में शामिल हैं : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, तिलहन, दलहन, पाम तेल और मक्का पर एकीकृत योजनाएं, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, ई-मार्केटप्लेस, और साथ ही एक विशाल सिंचाई एवं मृदा और जल संचयन परियोजना जिसके अंतर्गत, ९ करोड़ हैक्टेयर की वर्तमान सिंचित कृषि भूमि को वर्ष २०१७ तक बढ़ाकर १०.३ करोड़ हैक्टेयर किए जाने का लक्ष्य है।

सरकार ने पिछले दो दषकों में कुपोषण का सामना करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे कि स्कूलों में मिड-डे मील, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आंगनवाड़ी के ज़रिए राशन देना, और गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मायम से रियायती दरों पर अनाज उपलब कराना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, २०१३ का उेश्य है, इससे जुड़ी स्कीमों और परियोजनाओं के मायम से, सबसे संवेदनशील लोगों को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित कराना। इसके अंतर्गत, खाद्यान्न तक पहुंच को कानूनी अकिार बनाया गया है।

संयुक्त राष्ट्र का सहयोग

भारत में पोषण और आजीविका की जुड़ी हुई चुनौतियों को संबोति करने और यह सुनिश्चित करने कि संवेदनशील समूह पिछड़े न रह जाएं, संयुक्त राष्ट्र प्राथमिकता समूह सरकार के साथ सहभागिता में

पोषण सेवाओं को उचित अनुपात में बढ़ाने और घरों में खिलाने और देखभाल की प्रथाओं को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए सरकारी प्रयासों में मदद दे रही है, और साथ ही छोटे व सीमांत कृषि परिवारों की कृषि से होने वाली आमदनी बढ़ाने के लिए काम कर रही है। यह समूह गरीबी–उन्मूलन कार्यक्रमों के कृषि और आजीविका से जुड़े आयामों को सशक्त करने के लिए सहयोग करता है, विशेषकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए। पिछले वर्षो में, समूह ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सहभागिता में, गेहूं के आटे के दृढ़ीकरण पर एक राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन किया, और खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राकिरण के साथ मिलकर राष्ट्रीय खाद्य दृढ़िकरण नीति पर एक कार्यशाला भी आयोजित की।

यूनिसेफ के नेतृत्व में, प्राथमिकता समूह के सदस्यों में शामिल हैं, फूड ऐंड एग्रीकल्चर ऑरगनाईज़ेशन, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल लेबर ऑरगनाइज़ेशन, इंटरनेशनल ऑरगनाइज़ेशन फॉर माइग्रेशन, युनाइटेड नेशन्स एन्टिटी फॉर जेन्डर इक्वॉलिटि ऐंड दि एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, युनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, युनाइटेड नेशन्स एज्युकेशनल, साइंटिफिक ऐंड कल्चरल ऑरगनाइज़ेशन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम।

स्रोत: <https://in.one.un.org/un-priority-areas-in-india/nutrition-and-food-security/>

उधार लो, बचाओ, आपस में बांटों: ३ तरीके जिससे हमारी खाद्य प्रणाली लोकतांत्रिक बन सकती है

मूल रूप से येस मेग्ज़ीन में प्रकाशित, लेखक – नील थापर।

हमारी खाद्य प्रणाली टूट चुकी है और उसे जोड़ना ज़रूरी है – ऐसा कई लोगों का कहना है। लेकिन यह टूटी नहीं है। असल में, मेरा सोचना है कि यह बिल्कुल उसी तरह से काम कर रही है, जैसा कि इसके पीछे सोच थी। वर्तमान खाद्य प्रणाली, और उसका नियंत्रण करने वाले कानूनी नियम, विशाल उत्पादकों, विक्रेताओं, और निर्माताओं द्वारा और उनके लिए ही बनाए गए हैं। जितना बड़ा उतना बेहतर, इस विचार पर आधारित हैं, और यही कारण है कि हमारी खाद्य अर्थव्यवस्था पर विशाल, तेजी से समेकित होती हुई और लंबवर्ती एकीकृत कॉरपोरेशनों का नियंत्रण है।

हमारी खाद्य प्रणाली का एक विशेष रूप से समेकित क्षेत्र है बीज अर्थव्यवस्था; उदाहरण के लिए, केवल ६ कंपनियां ६३ प्रतिशत व्यापारिक बीज बाज़ार पर नियंत्रण रखती हैं। चूंकि हमारे भोजन में से अधिकांश की शुरुआत बीज के रूप में होती है, तो ज़्यादातर लोगों, जानवरों, या हमारे ग्रह के काम न आने वाली व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश करने से अच्छा है, कि हम अपनी खुद की व्यवस्था का निर्माण करें।

अगर हम स्वास्थ्यवर्धक, सस्ते, स्थानीय रूप से छोटे किसानों, जो कि प्राकृतिक संसाानों का ज़िम्मेदारी से उपयोग करते हैं, द्वारा उत्पन्न खाद्यान्न तक तुल्य पहुंच स्थापित करना चाहते हैं, तो हमें यही करना होगा। काम बड़ा है, लेकिन पूरा किया जा सकता है, विशेषकर यदि हम सब सही दिशा में काम करने का प्रण ले लें। यहां तीन आसान कदम दिए जा रहे हैं, जिससे हम अपनी बीज व्यवस्था और अपने आस–पड़ोस में लोकतंत्र को वापस ला सकते हैं।

१. उधार लो

यदि आप हाल में अपने स्थानीय पुस्तकालय नहीं गए हैं, तो आप यह जान कर हैरान होंगे कि वहां पर एक बीज लाइब्रेरी की व्यवस्था मौजूद है। पूरे संयुक्त राष्ट्र में, लगभग ४०० ऐसे समुदाय–आधारित बीज साझा करने के प्रयास चल रहे हैं, जहां पड़ोसी एक–दूसरे के साथ बीज बांट रहे हैं। यह इस प्रकार से काम करता है: आप बीज उधार लें, पौी उगाएं, जितना फल (जिसे आप खाते हैं!) पैदा होता है उसे इका करें, और कुछ बीज बचाकर कुछ बीज लाइब्रेरी को वापस कर दें, जहां अन्य लोग इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। असाधारण बीज लाइब्रेरियन रेबेका न्यूबर्न, जो रिचमंड ग्रोज़ सीड लेन्डिंग लाइब्रेरी की सह–संस्थापक हैं, इसे इस प्रकार कहती हैं: ''यह एक नई किताब को परखने की तरह ही है, बस इतना है कि आप जब किताब को वापस करते हैं, तो उसमें एक और अयाय जुड़ जाता है।

बीज लाइब्रेरी आम लोगों को नि:शुल्क बीज उपलब कराती है, जो पारस्परिकता और आपसी निर्भरता की भावना पर निर्भर करते हुए यह सुनिश्चित करती है कि उसके भंडार को लोग लगातार भरते रहें। सार्वजनिक लाभ के लिए बीजों को एक सामुदायिक संसाान के रूप में भंडारण करते हुए, इस प्रकार की सभी लाइब्रेरी एक ऐसा संसाान बना रही हैं, जिसे बीज संचायन कहा जा सकता है। संचायन से बीजों के संदर्भ में हमारी भूमिका स्वामी से बदल कर देखभाल करने वाले में तब्दील हो जाती है। जहां स्वामियों की ज़िम्मेदारी केवल उनके खुद तक ही सीमित होती है, देखभाल करने वालों की ज़िम्मेदारी बीजों और उस समुदाय के प्रति होती है, जिसने उनकी अभिरक्षा में यह बीज दिए। बीजों को संचायन के अंतर्गत लाकर, हमारे पास शक्ति है कि हम हमारी एक मूलभूत ज़रूरत: खाद्यान्न, तक पहुंच, और नियंत्रण को लोकतांत्रिक रूप दे सकते हैं।

२. बचाओ

बीजों को बचाना कुछ नया नहीं है। यह शायद सबसे पुरानी मानवीय परंपरा है, जो लगभग १०,००० वर्षों से चली आ रही है। पिछले

लगभग सौ वर्षो में, हमने सामाजिक रूप से, बीजों से अपने रिश्ते को खो दिया है। इस बीच, बीज एक संचायती संसाान न रहकर, एक व्यापार की वस्तु बन गए, जिनका स्वामित्व और बेचने का अकिार रखने वाली कंपनियों की संख्या कम से कम होती जा रही है।

लेकिन बीज को बचाना हमेशा आसान नहीं होता। इसीलिए लाइब्रेरी बनाई गई हैं, जो कि शिक्षात्मक संसाान के रूप में हमें बीज बचाने की कला और दक्षता को पुन: विकसित करने में मदद करती हैं। अपनी दक्षता को पुन: विकसित करने का मतलब है कि हम खुद को और अपने परिवारों को स्वस्थ खाना उपलब करा सकते हैं, जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए सामुदायिक तन्यकता का निर्माण कर सकते हैं, और हमारे पास जो बीज हैं उनके सांस्कृतिक इतिहास और महत्व को पुन: जान सकते हैं।

इसका यह भी मतलब है कि हम अपने खुद के लिए और अपने समुदायों के लिए खाना उगाएं। जितना खाना हम खुद पैदा करेंगे, उतना ही हमें भूमण्डलीय खाद्य प्रणाली पर कम निर्भर करना पड़ेगा, जो पर्यावरणीय, मानवीय या जानवरों के कल्याण से ज़्यादा मुनाफ़े को प्राथमिकता देती है। इसका यह भी मतलब है कि हम स्थानीय स्तर पर खाद्य पदार्थो को खरीदें और बेचें, जहां हमारा पैसा हमारे समुदाय के बीच ही रहे और इससे स्थानीय संपत्ति का निर्माण हो। बीज बचाना अपने आप में प्रतिरोा और नवीकरण का काम है।

३. बांटों

हमारी नई खाद्य प्रणाली की सफलता वर्तमान प्रणाली पर हमारी निर्भरता और एक–दूसरे पर पारस्परिक निर्भरता पर आधारित है। आसान शब्दों में, इसका मतलब है कि हमें और ज़्यादा बांटना चाहिए और तुल्यता के साथ बांटना चाहिए। हमें खतरे और पुरस्कार, मुनाफ़े और नुक्सान, प्रयास और परिणाम सब बांटने चाहिए। बांटने से, हम एक वैकल्पिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने लगते हैं, जो कि उत्पाद या सेवाओं के बदले पैसा देने पर आधारित न होकर, रिश्तों, उपहार देने, और पारस्परिक सहयोग पर आधारित है। ऐसे समय, जब हमारी अर्थव्यवस्था में पैसे की कमी बढ़ती जा रही है और पैसा कुछ अमीर लोगों के हाथों में जमा होता जा रहा है, बांटना हमें अपने लिए उपलबता बनाने का साान देता है।

बीजों को बांटने की शुरुआत करना विशेष रूप से आसान है, क्योंकि बीजों की प्रकृति ही ऐसी है जो बांटने के लिए बनी है। एक टमाटर का पौाा ५०० से ज़्यादा बीज पैदा करता है, जिन्हें सैान्तिक रूप से अगले मौसम में ५०० अलग–अलग उद्यानों में लगाया जा सकता है। अब, कल्पना करें कि १०० घरों में से प्रत्येक घर ५ ऐसी फसलें लगाता है और उनके बीजों को बांटता है। समुदाय–आधारित बीजों को बांटने से कुल स्थानीय खाद्य उत्पादन में इसका कितना गुणा प्रभाव होगा, उसका अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है!

लेकिन कोई भी अच्छा काम सज़ा के बिना नहीं जा सकता। फिल्हाल, पूरे देश की बीज लाइब्रेरी स्थानीय स्तर पर बीज बांटने की क्षमता की सुरक्षा करने के लिए जूझ रही हैं। अन्य लोगों के साथ साझेदारी में, सस्टेनेबल इकॉनमीज़ लॉ सेन्टर, जहां हम काम करते हैं, एक अभियान चला रहा है जिससे कि इस संघर्ष के बारे में जागरुकता फैले और बीज बांटने वाली संस्थाओं की ओर से जनवकालत कर रहा है। इसके बारे में और अकि जानकारी के लिए आप हमारी सेव सीड शेयरिंग वैबसाइट पर जा सकते हैं।

नीचे से ऊपर के क्रम में लोकतंत्र का निर्माण करने का मतलब है कि हमें केवल सरकार में ही नहीं, बल्कि अपने जीवन के हर पहलू में लोकतंत्र की कल्पना करनी होगी। नागरिक भागीदारी केवल वोट देने में चुनाव करने तक ही सीमित नहीं है – इसमें शामिल है कि हम कहां और कैसे अपना पैसा खर्च करना चाहते हैं। बीज लाइब्रेरी हमें मौका देती हैं कि हम खाद्य अर्थव्यवस्था में लोकतंत्र को वापस लाकर, बीज संचायन को पुन: प्राप्त करके, और स्थानीय खाद्य प्रणालियां बनाने के लिए समुदायों को सशक्त करके अपनी नागरिक भागीदारी को बढ़ा सकें।

नील थापर ने यह लेख येस! पत्रिका के लिए लिखा था। नील सस्टेनेबल इकॉनमीज़ लॉ सेन्टर में वक़ील के रूप में कार्यरत हैं और वहां फूड ऐंड फार्मलेंड्स परियोजना का नेतृत्व करते हैं। वह स्वस्थ, न्यायपूर्ण और तन्यकतापूर्ण खाद्य प्रणालियां बनाने के प्रति सामूहिक शक्ति बढ़ाने के प्रति गर्मजोशी से कार्यरत हैं। @NeilThapar <https://twitter.com/NeilThapar ट्विटर पर उन्हें फॉलो करें।

स्रोत : <https://www.radicalecologicaldemocracy.org/borrow-save-share-seeds/>

✦✦

३. आयोजन

मोबाइल जैवविविता उत्सव ... दलित औरतों का २० वर्षो से चला आ रहा उत्कृष्ट प्रयास

प्रेस विज्ञप्ति (डेक्कन डेवलपमेंट सोसायटी द्वारा)
फरवरी १५, २०२०

दो दशकों से चले आ रहे मोबाइल जैवविविता उत्सव के समापन समारोह, जो कि मचुनूर, झारसंगम में १५ फरवरी, २०२० को आयोजित किया गया, का अंत महत्वपूर्ण ज़हीराबाद एजेंडा के विमोचन के साथ हुआ। अपनी शुरुआत में, मोबाइल जैवविविता उत्सव ने भारत सरकार की राष्ट्रीय जैवविविता रणनीति और कार्ययोजना को जन्म दिया और अपने २०वें वर्ष में, इसमें ज़हीराबाद एजेंडा निकाला गया, एक ऐसा दस्तावेज़ जिसमें भूमण्डलीय समस्याओं और जलवायु परिवर्तन के स्थानीय समाधानों पर विमर्श किया गया है।

अपने २० वर्षो के सफ़र में, मोबाइल जैवविविधता उत्सव को देश में सबसे लंबे चलने वाले समुदाय–नेतृत्व वाले सांस्कृतिक अभियान के रूप में मान्यता मिली। इस उत्सव, जिसकी आत्मा क्षेत्र की सांस्कृतिक जड़ों में है, की शुरुआत दो गानों से हुई: एक संघम औरतों की पुरानी पीढ़ी का गाना और एक युवा पीढ़ी का गाना। जहां बड़ों ने आशा का गाना गाया, जो उनकी विशिष्ट जैवविवि फसल पति को अगली पीढ़ी द्वारा जारी रखने के बारे में है, वहां युवाओं ने व्यक्त किया कि उन्होंने किस प्रकार अपनी पारंपरिक कृषि पतियों को जारी रखने की ज़िम्मेदारी, बीजों को रखने और अपने समुदाय व वन्यजीवों के लिए खाद्य, पोषण की ज़िम्मेदारी और अपने परिवारों के लिए सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी लेते हुए, अपनी मांओं से आशा प्राप्त की है।

जैवविविध कृषक श्रीमति. अन्नपूर्णा कहती हैं, ‘जैवविविध फसलें लगाने के इतने सारे लाभ हैं क्योंकि कुछ फसलें खाद देती हैं, कुछ उनकी ज़डों के लिए उपयोगी हैं, कुछ खाना देती हैं, कुछ अन्य खाना उपलब कराती हैं और बाकी हमारे मवेशियों के लिए उपयोगी हैं। प्रत्येक जीवन को बनाए रखने के लिए हमें विभिन्न फसलें पैदा करनी चाहिए। हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए बीज पैदा और बचाने चाहिए। वह पक्षियों के लिए खाना भी बन जाता है। मेरे पति कहते हैं, हमें खुश होना चाहिए कि हम पक्षियों और जानवरों को खिला रहे हैं, क्योंकि वे हमारे घरों में शांति लाते हैं।

डेक्कन डेवलपमेंट सोसायटी के निर्देशक श्री. पी.वी.सतीश बोले, ‘इस वर्ष इस उत्सव को मनाने का हमारा एक विशेष कारण है। हमें जलवायु परिवर्तन के लिए स्थानीय, पर्यावरणीय, सतत और स्थायी समाधान ढूंढने के लिए इक्वेटर से सम्मानित किया गया है। इस मान्यता से, हम एक बार फिर खुद को याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे पास अपने समाधान हैं और हमें उन्हें जल्दी सतत बनाकर जलवायु संकट से लड़ना होगा, जिसके कारण डी.डी. एस. ने ज़हीराबाद एजेंडा तैयार किया। डी.डी.एस. का एजेन्डा कुछ गिने–चुने लोगों ने नहीं बनाया, बल्कि यह सैंकड़ों किसानों का एजेन्डा है, इस ज़मीन और इसकी विरासत का एजेन्डा है। १०,००० से आकि लोगों और ज़हीराबाद के १५८ सरपंचों ने इस एजेन्डा का समर्थन किया है। इस अभियान ने हमारे काम को करते रहने के लिए ऊर्जा को और बढ़ा दिया है। जैवविविधता उत्सव जलवायु संकट को जैवविविध कृषि के मायम से हल करने के इस समुदाय–आधारित अभियान का एक हिस्सा है।

आशीष कोठारी, पर्यावरणविद् और कल्पवृक्ष, पुणे के संस्थापक, ने बीस वर्षो बाद जैवविविधता उत्सव में भाग लेने के बाद याद करते हुए, और डी.डी.एस. के ज़हीराबाद एजेन्डा की सराहना करते हुए कहा कि यह दस्तावेज़ स्थानीय साधारण लोगों ने तैयार किया है, जो असाधारण काम करते हैं। कई प्रकार के संकटों, जैसे कि जलवायु संकट, जैवविविधता को खतरे, असमानता और घृणा की राजनीति के बारे में बात करते हुए, उन्होंने बताया कि लोगों की पारंपरिक और

आशीष कोठारी

आशीष कोठारी

आशिष कोठारी

आशिष कोठारी

आशिष कोठारी

आशिष कोठारी

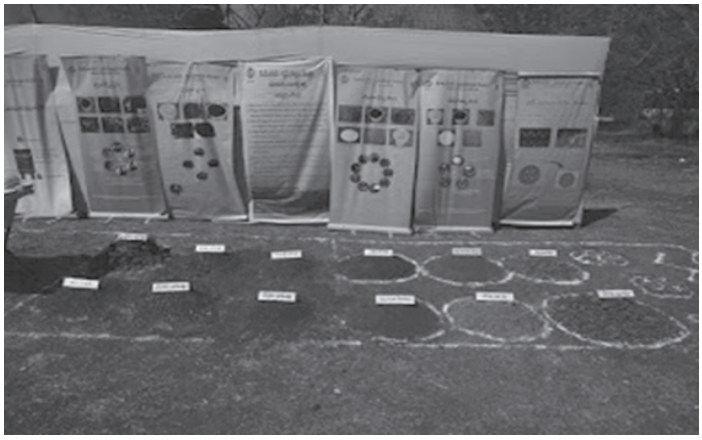

आशिष कोठारी

आशिष कोठारी

आशिष कोठारी

आशिष कोठारी

सांस्कृतिक प्रथाओं पर आधारित प्रक्रियाएं, जैसे कि डी.डी.एस. के संघम, ही भविष्य में इन सब संकटों का समाधान देंगे। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि जहां केन्द्र की नीतियां लोगों और जैवविविधता को बांटने का काम कर रही हैं, वहां डी.डी.एस. जैसे समुदाय ऐसे अभियानों के ज़रिए लोगों और विविाता, संस्कृति और जीवन के बीच जुड़ाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जिन-जिन औरतों का सम्मान किया गया वे सभी कलाकार हैं, किसान हैं, वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, जो कि हम सोचते हैं कि केवल शहरों में होते हैं। आप सब में यह सभी किरदार समाए हुए हैं, जिससे मैं इतने वर्षो से प्रेरित होता आया हूं।

रुक्मिणी राव, ग्राम्य महिला संसाान केन्द्र की निर्देशक, ने प्रकाश डाला कि इस क्षेत्र की महिलाएं तुलनात्मक रूप से ज़्यादा शक्तिशाली हैं क्योंकि वे पारंपरिक फसलें पैदा करती हैं, और खाती हैं। स्वीकारते हुए कि औरतें ही ज़मीन की ७० प्रतिशत ज़िम्मेदारी संभालती हैं, उन्होंने सुझाव दिया कि औरतों को ज़मीन का उत्तराकिारी बनाया जाना चाहिए, हमेशा की तरह पुरुषों को नहीं। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा, कि जैवविविाता उत्सव केवल मोटे अनाज का उत्सव ही नहीं, बल्कि औरतों का उत्सव भी है जिसमें वे अपने संघमों में और औरतों को जोड़ने तथा कृषि जारी रखने की ज़िम्मेदारी उठाएंगी।

माइकल पिम्बर्ट, निर्देशक, सेन्टर फॉर एग्रोइकॉलजी, वॉटर ऐंड रेज़िलियन्स, कवन्ट्री यूनिवर्सिटी, यू.के. ने ज़हीराबाद एजेन्डा की जलवायु संकट के लिए प्रासंगिकता के बारे में बात करते हुए बताया कि किस प्रकार यह एन्टार्कटिका और दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्रों में बढ़ते तापमान के लिए समाधान उपलब कराता है। संकट की तीव्रता के बावजूद, सरकारों के पास कोई जवाब नहीं है और वे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को नकार रही हैं, जलवायु परिवर्तन को नकार रही हैं और जो आंदोलन इस विषय पर बात कर रहे हैं, उन्हें हतोत्साहित कर रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एजेन्डा औरतों के ज्ञान को रेखांकित करता है तथा यह नीचे से ऊपर की दिशा की प्रक्रिया है जिसमें बाज़ार या सरकार शामिल नहीं है, बल्कि लोग शामिल हैं। अाकि दिलचस्प है प्रक्रियाओं के बारे में सोचना, यह सोचना कि पूरी व्यवस्था भू-दृश्य, पारंपरिक संस्थानों, रिवाज़ों और ाार्मिक प्रथाओं से जुड़ी हुई है, जिससे सामाजिक सुरक्षा पैदा होती है। उल्लेखनीय है कि ज़हीराबाद लोक एजेन्डा को सरकार से समर्थन मिला है; १६० सरपंचों से। मैं सरकार के समर्थन को सलाम देना चाहता हूं। स्थानीय प्रशासन बहुत कुछ हासिल कर सकता है यदि वह स्थानीय समुदायों को अपने खुद के समाधान ढूंढने के लिए संगठित होने में सहयोग करें। महत्वपूर्ण है कि समुदायों और सरकार के बीच सहभागिता से क्षेत्र में ज़्यादा समाधान और शांति प्राप्त की जा सकती है। ज़हीराबाद एजेन्डा ने स्थानीय समाधान ढूंढने में नए आयाम स्थापित किए हैं और यह इस क्षेत्र से बहुत आगे तक जाएगा तथा कई अन्य लोगों को प्रेरित करेगा।

हनुमंता राव, कलेक्टर और ज़िला न्यायाीश, संगरेड्डी ज़िला, ने डी.डी.एस. को ज़हीराबाद एजेन्डा जारी करने पर बाई देते हुए कहा कि यह एजेन्डा स्थानीय लोगों से आया है जो कि जलवायु परिवर्तन के भूमण्डलीय संकट को चुनौती देगा। सरपंच लोगों का अंतिम प्रतिनिाि होता है, इसलिए १६० सरपंचों से आपके काम की मान्यता प्राप्त करना उल्लेखनीय और प्रेरणादायक है। डी.डी.एस. ने अपने ज़िले को भूमण्डलीय मानचित्र पर चित्रित कर दिया है और ज़हीराबाद एजेन्डा विश्व भर के लिए दिशा तय करेगा, यह महत्वपूर्ण है कि यह नीचे से ऊपर की ओर दिया गया एजेन्डा है, जो कि बड़े शहरों में विकसित किए हुए एजेन्डा से अलग है। आपके द्वारा पैदा किए गए खाद्यान्न को बेच पाना बहुत ज़रूरी है और हमें 'बीयोन्ड ऑर्गेनिक जैसी परियोजनाओं को बढ़ावा देना चाहिए। हमें जंगल बढ़ाने होंगे और जैसा कि अल्गोले रत्नाम्मा जैसी औरतों ने पथरीले क्षेत्र में जंगल उगाया है, वह सराहनीय है।

दूसरा मुा है अनीमिया, जिसे मोटे अनाज की खेती और अययन को बढ़ावा देकर आंगनबाड़ियों में मोटे अनाज के उपयोग तथा इनकी

मात्रा बढ़ाए जाने के ज़रिए हल किया जा सकता है। मैं ऐसे ज़िले का प्रतिनिधि होने में गर्व महसूस करता हूं जिसमें डी.डी.एस. काम करती है, जिसके कारण हमारा ज़िला आज विश्व के मानचित्र पर चिह्नित किया जा रहा है। मैं ज़हीराबाद एजेन्डा को बढ़ावा देने के लिए काम करूंगा और इसके लिए अपना पूरा सहयोग देता हूं।

डा.संजय माथुर, एजेन्डा लोगों की सोच है लेकिन एजेन्डा को वास्तविकता बनाने के लिए संस्थागत प्रणाली की आवश्यकता है। और ज़िला कलेक्टर जैसे सरकारी अफसरों के अलावा और किसी के पास यह शक्ति नहीं है। और मैं, एक शिक्षाविद् होने के नाते कलेक्टर से अनुरोध करता हूं कि वे ज़िला प्रणालियों के मायम से ज़हीराबाद एजेन्डा को आगे ले जाने में सहयोग करें।

स्रोत:<https://ashishkothari51.blogspot.com/2020/02/mobile-biodiversity-festival-dalit.html>

✦✦

४. आशा के संकेत

कच्छ के वागड़ या काला कपास : (लगभग) मौत से वापस

खमीर

एक समय था जब कच्छ के अर्ा–शुष्क मैदानी इलाके में ऐसे पौधे उगते थे जिनमें देसी वागड़ कपास के नर्म सफ़ेद गुच्छे लगते थे। कपास की नर्मी उसके कठोर नाम से बिल्कुल विपरीत थी – उसे बहुत कम पानी की ज़रूरत होती थी, कोई कीटनाशक दवा नहीं, और कुल मिलाकर, बहुत कम देखरेख – आज की सूखे और पानी की कमी की स्थिति के लिए एकदम सही।

लेकिन, लंबे रेशे वाली अमरीकी किस्म का कपास आने के बाद, वागड़ जैसी देसी कपास की किस्मों की लोकप्रियता खोने लगी, जब तक कि वह लगभग लुप्त नहीं हो गईं। इन छोटी रेशे वाली, देसी कपास की किस्मों को पुनर्जीवित करने का एक प्रयास – विशेषकर जब बी.टी. कपास का आकर्षण खत्म हो रहा है और पानी की कमी एक कड़वी सच्चाई बनती जा रही है – धीरे–धीरे फल दे रहा है।

बदलती प्रक्रियाएं

भरतीय स्वतंत्रता के समय देसी कपास और अमरीकी कपास का अनुपात ९७:३ था। ''आज, वी.एन.वाघमरे, निर्देशक केन्द्रीय कपास अनुसाांन संस्थान, नागपुर कहते हैं, ''यह अनुपात उल्टा हो गया है। देसी कपास घट कर केवल ३ प्रतिशत रह गया है।

अमरीकी कपास के पक्ष में बहुत से पहलू काम कर रहे थे – ''उसके गुच्छे का आकार काफ़ी बड़ा होता है और उसे इका करना आसान होता है, वाघमरे कहते हैं – जबकि देसी किस्म का गुच्छा छोटा होता है और उसे इका करने में बहुत मेहनत लगती है।

''शुरु में, देसी कपास के रेशे की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं थी और इसके कारण अमरीकी कपास पर और अनुसाांन किया गया, वाघमरे ने बताया। ''१९७१ में, पहली हाइब्रिड कपास की किस्म जारी की गई। इसके कारण देसी कपास के क्षेत्रफल में और कमी आ गई।

कच्छ की वागड़ कपास के साथ भी यही हुआ। नई किस्मों के मुकाबले, कम पैदावार एक मुा था और जैसा कि मावजीभाई पार, कच्छ के एक किसान और मिल मालिक का कहना है, ''जब ड्रिप सिंचाई और नर्मदा से पानी की उपलबता हो गई, तो किसानों ने बारिश से सिंचित वागड़ किस्म को छोड़कर, सिंचाई वाली कपास की किस्में लगाना शुरु कर दिया।

खमीर

खेत में काला कपास।

बाज़ार में इसकी मांग में कमी का एक अन्य कारण था कि अन्य देसी कपास किस्मों की तरह ही, वागड़ कपास छोटे रेशे वाली किस्म है। लंबे रेशे वाली किस्म के मुकाबले, इससे खुरदुरा कपड़ा बनता है। विडंबना यह है कि ''लोक कपास के इसी खुरदुरेपन, जिसे हम पहले पहनने के आदि थे और यही देश के मौसम के लिए अनुकूल थी, के कारण इसका पतन हो गया।

सात्विक, जैविक खेती पर काम करने वाली एक संस्था, के शैलेष व्यास ने कहा, ''कम पैदावार इतना बड़ा मु्दा नहीं था जितना कि इसका महत्व खत्म होना। ''१९८७ में, हमने सबसे बुरा सूखा देखा – भुज में केवल २ मि.मि. बारिश हुई। तब भी वागड़ कपास की पैदावार ३.५ मी.टन थी, उन्होंने कहा, ''लेकिन एक बार उसका महत्व खत्म हो गया, तो उसकी कीमतों में मंदी आ गई। इसे आधुनिक–ज़माने–का–नहीं–है कपास के रूप में जाना जाने लगा।

विडंबना यह है कि देसी कपास, जिसकी बेहतरीन कपड़े के उत्पादन की ५००० साल पुरानी विरासत है, यहां तक कि मलमल बनाने की भी, उसका महत्व खत्म हो गया। मीना मेनन, पत्रकार और अ फ्रेड हिस्ट्री : द जर्नी ऑफ कॉटन इन इंडिया नामक किताब कि सह–लेखक, का कहना है कि औपनिवेशकाल में, लंबे रेशे वाली किस्म जिससे बारीक कपड़ा बनता था, उसे अंग्रेज़ लेकर आए थे।

''मिलें लगाई गईं और लंबे रेशे वाले कपास को इतना प्रोत्साहन दिया जाता था कि किसानों ने खाद्य फसलें छोड़कर कपास उगाना शुरु कर दिया, उन्होंने कहा।

जहां एक समय रोज़मर्रा पहना जाने वाला कपड़ा इससे बनाया जाता था, अब वागड़ केवल गे और पयिां बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। ''इस सब से देसी कपास किसानों, बुनकरों, प्राकृतिक रंगरेज़ों और बाज़ार के बीच की उत्कृष्ट मूल्य ृंखला टूट गई, खमीर संस्था, जिसने एक दशक पहले वागड़ कपास को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया शुरु की, के घटित लेहरू ने बताया।

लेकिन पूरी तरह से उम्मीद खत्म नहीं हुई है।
निष्पक्षता से कहा जाए, तो वागड़ कच्छ से पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी, हांलाकि उसका पतन तेज़ी से हो रहा था। सी.आई.सी.आर. के विज़न कवर २०५० के अनुसार, गुजरात में कपास का क्षेत्रफल वर्ष २००० में १५.७ लाख हैक्टेयर से वर्ष २०११ तक दोगुणा होकर ३०.३ लाख हैक्टेयर हो गया। ''गुजरात में लगभग ५० प्रतिशत कपास की खेती सिंचित है, रिपोर्ट में लिखा गया है।

लेकिन बारिश से सिंचित वागड़ कपास कच्छ के रापड़ और बचऊ तालुकाओं में उगाया जाता है, मुख्यत: क्योंकि ''इन क्षेत्रों में पानी की कमी है और सिंचित खेती अभी तक उन के पास नहीं पहुंची है। वागड़ के लिए कम पानी की ज़रूरत होती है, जो कि बी.टी. कपास से अलग है, और यह कीड़ों और बीमारियों से भी सुरक्षित प्रजाति है। ''यह द्विगुणित है, बल्कि बी.टी. कपास चतुर्गुणित, जिसका मतलब है कि इसे पर–परागण की आवश्यकता नहीं होती और यह स्व–संरक्षित किस्म है, सात्विक के व्यास ने बताया।

वागड़ को आमतौर पर सितंबर माह में बीजारोपण किया जाता है और फरवरी के आसपास फ़सल को काटा जाता है। रापड़ में लगभग २५०० किसान वागड़ कपास उगाते हैं, सेतु अभियान संस्था के देवसी परमार ने बताया।

''फिर भी संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी, परमार, जो खुद भी किसान हैं, ने बताया। ''लगभग २०–२५ वर्ष पहले, रापड़ के लगभग २० गांवों में, ५०,००० किसानों में से २५,००० वागड़ कपास लगाते थे। यहां, हांलाकि पानी की समस्या के कारण बी.टी. कपास का मुद्दा नहीं था, लेकिन किसानों ने वागड़ कपास के बदले अन्य फसलें, जैसे कि अरंडी और गवार फली लगाना शुरु कर दिया क्योंकि उनकी बाज़ार में अच्छी कीमत मिलती थी, उन्होंने बताया।

लगभग दो दशक पहले, वागड़ कपास के लिए रु.१३००–१४०० प्रति ४० किलो (१ मन) की कीमत मिल जाती थी; दस वर्ष पहले यह कीमतें गिरकर रु.६००–७०० प्रति ४० किलो हो गईं।

कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि रापड़ के कल्यानभाई नाथूभाई जैसे किसान, जो किसी समय में अपने ३५ एकड़ के खेत में से २० एकड़ में वागड़ कपास लगाया करते थे, उन्होंने धीरे–धीरे देसी कपास की खेती को कम करके उसके बदले ज़्यादा फायदे वाली फसलें, जैसे कि अरंडी, लगाना शुरु कर दिया। सेतु जैसी संस्थाओं ने इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए मिति फसलें लगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की कोशिश की – उदाहरण के लिए, वागड़ कपास के साथ अरंडी, मूंग और बाजरा – जिससे कि उनका नुक्सान कम किया जा सके। मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए चक्रानुक्रम में फसलें उगाने – जहां एक वर्ष एक फसल उगाई जाती है और दूसरे वर्ष कोई अन्य फसल – का भी प्रयास किया गया।

खमीर

काला के ताने को नापते हुए।

लेकिन बाज़ार में गिरती मांग और कम कीमतों ने वागड़ कपास की किस्मत पर अंकुश जारी रखा। उदाहरण के लिए, रापड़ के एक गांव बाखेल ने देसी कपास की खेती बिल्कुल खत्म कर दी, जिसके कारण कच्छ में देसी कपास को वापस लाने में कार्यरत संस्थाओं के बीच खतरे की घंटी बज गई।

यह बाज़ार की ताकतों के बीच की सर्वोत्कृष्ट लड़ाई थी; मांग और आपूर्ति के बीच का संघर्ष। इससे निपटने के लिए, विभिन्न संस्थाओं ने कई प्रयास किए। उनमें से एक था इस कपास के लिए जैविक कपास का प्रमाणीकरण प्राप्त करना, जिसे कई विशेषज्ञ 'बाई डीफॉल्ट ऑर्गेनिक कहते हैं, क्योंकि इसके लिए किसान कोई कीटनाशक उपयोग नहीं करते।

पुनर्जीवन की ओर

''वागड़ कपास के लिए जैविक प्रमाणीकरण ने बाज़ार में उसके मूल्य को सुधारने में मदद की। यह २०११–१२ में हुआ और इसके कारण इस पुराने ज़माने के कपास को जिस नज़र से बाज़ार देखता था, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया, परमार ने बताया। इसका मूल्य रु.७०० प्रति ४० किलो से बढ़कर रु.१५००–१६०० प्रति ४० किलो तक बढ़ गया।

व्यास सहमत हैं कि प्रमाणीकरण ने वागड़ कपास पर यान आकर्षित करने और उसका महत्व बनाने में मदद की। इस बीच सात्विक विभिन्न मिलों से उनके बनाए कपड़े में वागड़ कपास उपयोग करने के लिए पक्ष–जुटाव का काम कर रहा था।

''हमने २००७–०८ में अरविंद मिल्स से वागड़ कपास के जैविक, मज़बूत, और थोड़ा खुरदुरा होने जैसे उत्कृष्ट पहलुओं के बारे में बात की। हमने तीन–चार साल मिलकर काम किया, व्यास ने बताया, और जोड़ा कि इससे बात फैलाने में मदद मिली कि इस पुराने ज़माने के कपास को आधुनिक ज़माने के कपड़े बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

''दुर्भाग्यवश, उसी समय यूरोप के जैविक बाज़ारों में आर्थिक मंदी छा गई और इसका प्रभाव हम पर भी पड़ा, उन्होंने बताया।

लगभग उसी समय, खमीर संस्था कच्छ में छोटे स्तर पर कार्यरत बुनकरों, जिनकी संख्या २००१ में कच्छ भूकंप के बाद तेज़ी से हुए औद्योगीकरण के कारण, १९९० में २००० से घटकर केवल ६००–७०० रह गई थी, को सहयोग करने के लिए विकल्पों की तलाश कर रही थी। बुनकर बदलते हुए बाज़ार के परिवेश का सामना नहीं कर पा रहे थे, और जैसा कि खमीर के घटित लेहरू ने कहा, वे सिंथेटिक रेशे के बदले एक स्थानीय, प्राकृतिक रेशे की तलाश कर रहे थे।

''उस समय सात्विक ने वागड़ कपास के बारे में हमसे संपर्क किया। यह मज़बूत था, स्थानीय और पर्यावरण अनुकूल भी था। हमने उसकी ब्रांड बनाने का निर्णय कर लिया और उसे नाम दिया काला कपास, लेहरू ने बताया।

वागड़ कपास को २०१०–११ में ''काला कपास का नाम दे दिया गया। 'काला का मतलब है कपास का बीजकोष – कपास का मूल।

खमीर के काला कपास प्रयास के साथ अन्य संस्थाएं, जैसे कि सेतु अभियान व अन्य भुटी जुड़ गईं, जिससे यह देशी कपास को पुनर्जीवित करने के एकल उद्देश्य के लिए एक सहयोगी प्रयास बन गया। छोटे स्तर पर शुरुआत करते हुए, खमीर ने ११ काला कपास किसानों के साथ काम करना शुरु किया और उन्हें एक छोटी मिल से जोड़ दिया, जो इस कपास के प्रति समर्पित थी।

मावजीभाई पार, इस मिल के मालिक, ने कहा, ''किसान अपनी उपज हमें भेजते हैं और हम उन्हें रु.१५००–१६०० प्रति ४० किलो मूल्य देते हैं।

बी.टी. कपास का मूल्य अभी भी ज़्यादा है – रु.२५०० प्रति ४० किलो – और उसका उत्पादन प्रति एकड़ खेत में लगभग ४० मन (१६०० किलो) होता है। काला कपास प्रति एकड़ २० मन (८०० मिलो) उत्पादन देता है। लेकिन अब पानी की कमी की वास्तविकता की स्थिति में, बी.टी. कपास की खेती प्रति एकड़ ३०–३५ मन ही रह गई है; और उसके साथ कीटनाशकों का खर्च अलग होता है। काला कपास उत्पादन की कोई कीमत नहीं होती – इसे केवल बीज लगाते समय बारिश की आवश्यकता होती है, मिल मालिक ने बताया। लेखक मीना मेनन ने कहा कि बी.टी. कपास ने द्वितीयक कीटों, जैसे कि व्हाईटफ्लाय की समस्या और पैदा कर दी है, जिससे कि और अधिक कीटनाशकों का उपयोग करना पड़ता है।

इस पुराने ज़माने के कपास को बढ़ावा देने के प्रयास में, खमीर हथकरघे को भी बढ़ावा दे रहा है और उन्होंने गेनरों को भी शामिल किया है, जिससे कि ''जो कड़ी टूट गई थी – किसान, गेनर, सूत कातने वाले, बुनकर, और अंततः बाज़ार – वह धीरे–धीरे फिर से स्थापित हो रही है।

काला कपास बुनते हुए राजा हाजा वंकर।

हांलाकि यहां तक का सफर आसान नहीं था।
काला कपास का छोटा रेशा उसका सूत बनाने और बुनने में मुश्किल पैदा करता है और शुरु में, खमीर और सात्विक को विशेषज्ञों से राय लेनी पड़ी कि इसका धागा कैसे बनाया जाए। बुनकरों को विश्वास दिलाना एक और चुनौती थी क्योंकि इसके लिए एक दूसरे प्रकार के करघे पर काम करना था।

कई सप्ताहों और वर्षो तक प्रक्रिया पर काम करते–करते, अंतत: खमीर ने वर्ष २०१० में काला कपास के उत्पादों का शुभारंभ किया। सतत कपड़े और फैशन, जो कि हाथ से बुना हुआ और प्राकृतिक रूप से रंगा हुआ है, की खासियत के साथ, खमीर ने डिज़ाइनरों के साथ भी काम करना शुरु किया और उन्हें अपना पहला ग्राहक बोंज ब्रांड की अर्चना शाह में मिला।

''शुरु में हम इस (काला कपास) को बहुत पतला बनाना चाहते थे, लेकिन फिर हमें अहसास हुआ कि इसकी खासियत इसके प्राकृतिक रूप में है। तो हमने निर्णय लिया कि हम इसके खुरदुरेपन को बरकरार रखेंगे, व्यास ने यह समझाते हुए बताया कि धागे की संख्या पर आधारित, कपड़े को कमीज़ या पतलून, या पर्दे/चादर आदि के लिए तैयार किया जा सकता है।

अब काला कपास प्रयास से और अकि किसान जुड़ गए हैं और २५० से ज़्यादा बुनकर इस पर काम कर रहे हैं। ''अब यह प्रणाली स्थापित हो गई है, उन्होंने कहा।

यह प्रयास, सी.आई.सी.आर. के वाघमरे कहते हैं, सही दिशा में किए जा रहे हैं। सी.आई.सी.आर. की विज़न कवर २०५० रिपोर्ट कहती है, ''वर्ष २०५० तक संभव है कि देसी कपास की किस्म गोसिपियम आरबोरियम उस क्षेत्र के अधिकांश हिस्से में उगाई जा रही हो, जो वर्तमान में अमरीकी कपास की किस्म जी. हिर्सुटुम के आीन है, विशेषकर जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली मौसम की अनियमितताओं और देसी कपास के ागे की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए व्यवस्थित प्रजनन प्रयासों के कारण।

इस वर्ष हमने देसी कपास की एक और किस्म जारी की है जिससे ४० क्विंटल कपास की उपज होती है, वाघमरे ने बताया।

जहां तक ज़मीनी स्तर पर किसानों का सवाल है, उनके लिए धीरे–धीरे स्थिति बेहतर हो रही है। ''हमने अपने पड़ोसी राज्यों, जैसे कि पंजाब, में देखा है कि अत्यधिक कीटनाशकों के उपयोग से ज़मीन का क्या हाल होता है, मावजीभाई ने कहा, ''हम नहीं चाहते कि हमारी ज़मीन और हमारी मिट्टी निर्जीव बन जाए।

मोंगाबे इंडिया में पहली बार जुलाई २०१९ में प्रकाशित हुआ।
स्रोत: http://vikalpsangam.org/article/kala-cotton-again/#.XljRpSEzbIU

✦✦

५. अंतर्राष्ट्रीय

शहर और देश के बीच: घरेलू कामगार खाद्य संप्रभुता का निर्माण कर रहे हैं
लेखक: केरेन पोमियर और तान्या करसेन

लेटिन अमेरीका और कैरेबियन में, महिला मज़दूरों में से १८ प्रतिशत घरेलू कामगार के रूप में काम करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन करके शहरों में काम की तलाश में आए इन लोगों में से अकितर ग्रामीण और शहरी, दोनों पहचानों को कायम रखते हैं। एक ओर अपने परिवार के खेतों के साथ गहरा जुड़ाव रखते हुए, और दूसरी ओर शहरी घरों में खाना बनाने और खरीदने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए, यह लोग खाद्य प्रणालियों में एक अहम स्थान रखते हैं। बोलिविया में, घरेलू कामगारों की सु–संगठित यूनियन अपने सदस्यों को सशक्त करने और शहरी उपभोक्ताओं को देसी खानों, स्वस्थ आहार, कृषि–पारिस्थितिकी, और छोटे खेतों की अर्थव्यवस्था को सहयोग देने के विषयों पर शिक्षित करने का काम कर रही हैं।

सित्राहो–एस.पी.

दक्षिणी विश्व के कई देशों की तरह, बोलिविया में भी पिछले दो दशकों में बड़े स्तर पर आंतरिक पलायन हुआ है – विशेषकर ग्रामीण कृषि क्षेत्रों से शहरों के बीच, जैसे कि राजाानी ला पाज़ में। वे शहरी, कामगारों और उपभोक्ताओं की ग्रामीण उत्पादकों के साथ एकजुटता के प्रति जागरुक हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों के पलायन के कारणों में नव–उदारवादी नीतियां शामिल हैं, जो किसानों द्वारा पैदा की गई फसलों की कीमतों, और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अवमूल्यन करते हुए, कृषि उत्पादन को अस्थिर बना देती हैं। परिणामस्वरूप, बोलिविया की कई कृषि परिवारों की औरतें काम की तलाश में शहरों को पलायन करने के लिए मजबूर हो जाती हैं – अक्सर १५ वर्ष आयु से पहले, जिन्होंने बहुत कम औपचारिक शिक्षा प्राप्त की है, और इनमें से कई आदिवासी पृष्ठभूमि से आती हैं। वास्तव में, ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को आमतौर पर पुरुषों के रूप में दर्शाया जाता है, लेकिन अब पलायन के 'स्त्रीकरण को तेज़ी से पहचाना जा रहा है।

सबसे बुरे मामलों में, यह संवेदनशील महिलाएं मानव तस्करी का शिकार बन जाती हैं। कुछ निजि स्तर पर घरों में घरेलू कामगार बन जाती हैं जिन्हें सफ़ाई, खाना बनाने और बच्चों तथा बूढ़ों की देखभाल का काम सौंप दिया जाता है। घरेलू कामगारों की स्थितियों में बहुत अंतर होता है, कहीं तो उन्हें लगभग गुलामों की तरह रखा जाता है, तो कहीं–कहीं उनकी काम की स्थितियां थोड़ी–बहुत गरिमापूर्ण होती हैं। लेकिन आमतौर पर, इस कार्यक्षेत्र, जिसमें अनुमानत: ७२,००० कामगार कार्यरत हैं, में से ९७ प्रतिशत औरतें हैं, के संघर्ष अदृश्य रहे हैं।

अक्सर अलग–थलग और अकेले रहने वाले घरेलू कामगारों को संगठित करने की चुनौतियों के बावजूद, उनके आिकारों की सुरक्षा करने के लिए उनकी यूनियन बनाने के काम में असाधारण सफलता मिली है। वर्ष १९९३ में, घरेलू कामगारों की यूनियन की राष्ट्रीय फेडरेशन की स्थापना हुई, जिसमें आज के दिन बोलिविया के नौ विभागों से १३ यूनियन शामिल हैं। यूनियन कामगारों और औरतों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए काम करती हैं, और अपने सदस्यों को शिक्षा तथा संसााान उपलब कराती हैं। यूनियन अपने सदस्यों, जो ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में जड़ें रखते हैं, के ग्रामीण क्षेत्रों और शहरों से जुड़ाव को मज़बूत करके, उन के आत्म–सम्मान बढ़ाने और सांस्कृतिक पहचान बनाने का काम करती हैं।

गरिमा और खाद्य संप्रभुता की खोज में घरेलू कामगार

वर्ष २००९ में, ला पाज़ की घरेलू कामगार यूनियन, सित्राहो ने गरिमा और खाद्य संप्रभुता की खोज में घरेलू कामगार परियोजना की शुरुआत की, जिसका उेश्य था अपने सदस्यों को खाद्य संप्रभुता के विषय पर राजनीतिक शिक्षा देना, और स्वस्थ, पारिस्थितिकीय रूप से उत्पादित आहार की बिक्री को बढ़ावा देना।

इंटरचर्च कोऑपरेटिव फॉर डेवलपमेंट कोऑपरेशन की मदद से, सित्राहो ने महिला घरेलू कामगारों के लिए अपना प्रैक्टिकल स्कूल खोला, जहां नेतृत्व कौशल, वित्तीय प्रबांन, और उद्यमिता का विकास करने पर कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इनमें से, गैस्ट्रोनॉमी ऐंड फूड सोवरेन्टी कार्यक्रम में यूनियन के २००० सदस्यों को पाक कला, खाद्य सुरक्षा, व अन्य व्यवहारिक खाद्य प्रबांन कुशलताओं पर प्रशिक्षण के साथ–साथ, खाद्य संप्रभुता के सिंातों की राजनीतिक शिक्षा दी जाती है। पाठ्यक्रम में स्थानीय उत्पादों के उपयोग, किसान परिवारों से सामग्रियां लेने, और देसी खानों के पुनर्मूल्यांकन पर ज़ोर दिया जाता है। फिर इन सिंातों को उन घरों में लागू किया जाता है जहां सित्राहो के सदस्य काम करते हैं, जिससे मयम और उच्च वर्गीय परिवारों में खाद्य संप्रभुता के मूल्यों का प्रसार होता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भोजन का काउंटर भी चलाया जाता है जहां स्वस्थ, पारिस्थितिकीय, स्थानीय स्रोतों से लाया गया, और सस्ता खाना उपलब कराया जाता है जिसका ज़ोर उपभोक्ता शिक्षा पर रहता है। ज़्यादातर उपभोक्ता सेन पेड्रो आवासीय क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, जहां पर यह रेस्तरां स्थित है, और इससे होने वाले मुनाफे को बेरोज़गार या बुज़ुर्ग यूनियन सदस्यों की मदद के लिए उपयोग किया जाता है।

ग्रामीण और आदिवासी पहचान

कई घरेलू कामगार अपने गांवों से नज़दीकी रिश्ता बनाए रखते हैं, जिनके परिवार के सदस्य अभी भी खेती करते हैं। वे किसानों की समस्याओं और शहरी, कामगारों और उपभोक्ताओं की ग्रामीण उत्पादकों के साथ एकजुटता की आवश्यकता के विषय में भली–भांति अवगत हैं। रोज़ालिया लाज़ो लाज़ो, जो कि १४ वर्ष की उम्र में ओमासूयोज़ ग्रामीण क्षेत्र से ला पाज़ आए थीं कहती हैं, ''२००९ में

घरेलू कामगारों के प्रेक्टिकल स्कूल को भोजन के समय रेस्तरां में तब्दील कर दिया जाता है।

शुरुआत करने के बाद से मैंने कई कृषकों और आदिवासी किसानों से बात की है और यह मुझे मेरे बचपन की याद दिलाते हुए मेरे मां–बाप के बारे में सोचने को मजबूर करता है, जो अभी भी खेतों में काम करते हैं।

कई घरेलू कामगार कीचुआ या आयमारा आदिवासी संस्कृति से हैं और वे आदिवासियों के देसी खानों जैसे कि किनुआ (केनोपोडियम किनुआ), कानाहुआ (कीनोपोडियम पैलिडिकौले), अकई (यूटर्पे ओलरेसिया) और मुना (मिन्थोस्टैकिस मौलिस) से वाक़िफ हैं। शहरी लोग अक्सर इन खानों के बारे में नहीं जानते, और न ही यह सुपरमार्केट में मिलते हैं, जहां ज़्यादातर आयातित उत्पाद और एक जैसे स्वाद और बनावट के संसाधित खाद्य पदार्थ ही बेचे जाते हैं। गरिमा और खाद्य संप्रभुता की खोज में घरेलू कामगार कार्यक्रम के मायम से, न केवल कामगार अपनी खाद्य संस्कृति के व्यंजनों का मूल्य पहचानते हैं, बल्कि वे अपने नियोक्ताओं को भी इन व्यंजनों की जानकारी देते हैं।

अक्सर घर के सभी खाद्य पदार्थ खरीदने और दिन में तीनों बार खाना बनाने की ज़िम्मेदारी घरेलू कामगारों की ही होती है। इससे उन्हें परिवार के भोजन के चयन पर काफ़ी नियंत्रण मिलता है, वे किस प्रकार की खाद्य प्रणालियों का सहयोग करते हैं, और वे कॉरपोरेट खाद्य श्रृंखलाओं को बढ़ावा देंगे या किसानों की अर्थव्यवस्था को। रोज़ालिया टिप्पणी करती हैं, ''मैं जानती हूं कि कृषि बहुत मुश्किल काम है और गांवों के लोगों को सहयोग की आवश्यकता है। मेरी मां अभी भी सुबह बहुत जल्दी उठती हैं क्योंकि उन्हें भेड़ों की देखभाल करनी होती है, और पाले या ओलों के कारण कभी–कभी उनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं। उपभोक्ता परिस्थितिकीय रूप से पैदा किए हुए उत्पादों को कोई महत्व नहीं देते, उसके बदले वे आयातित उत्पाद खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन मेरी पिछली नौकरी में, मैं बच्चों के लिए कानाहुआ खरीदती थी। बहुत मुश्किल था, क्योंकि वे बाज़ार की बेकार की चीज़ें खाना पसंद करते थे, लेकिन मैं उनसे कहती थी, क्या तुम बड़े होकर ताकतवर बनना नहीं चाहते? और फिर वे उसे खा लेते थे! अगर आप किसी चीज़ में विश्वास रखते हैं, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता।

परिवार के सदस्यों के साथ गठबांन

पिछले कुछ वर्षो में, सित्राहो ने महत्वपूर्ण खाद्य पैरवी समूहों, छोटे व्यवसायियों, और उत्पादकों की संस्थाओं के साथ सहभागिता की है, जिनमें शामिल हैं असोसिएशन ऑफ ऑर्गेनिक प्रड्यूसर्स ऑफ बोलिविया; दि कोऑर्डिनेशन ऑफ पेज़ेंट इकनॉमिक ऑर्गनाइज़ेशन्स; फन्डेसियाँ सरतावी जो कालामार्का नगरपालिका में सतत कृषि को बढ़ावा देने का काम करती है; माद्रे टिएरा, ला पाज़ में जैविक खाद्य पदार्थो की एक चेन; और स्लो फूड बोलिविया। सित्राहो इन छोटी किसान संस्थाओं और स्थानीय व्यापारियों से खाद्य पदार्थ लेने के प्रति वचनब है, जिससे कि स्थानीय खाद्य अर्थव्यवस्था मज़बूत हो और छोटे किसानों की मदद हो।

अक्तूबर २०१४ में, सित्राहो ने ला पाज़ के पहले नैतिक खाद्य मेले का सह–आयोजन किया। मेले में बेची जा रहे सभी व्यंजनों को पकाने की ज़िम्मेदारी सित्राहो की महिलाओं की थी, जिसके मायम से वे लोगों को गैर–जी.एम.ओ. और पारिस्थितिकी–अनुकूल तरीकों से पैदा की गई सामग्री, जिसे स्थानीय किसान संस्थाओं से प्राप्त किया गया था, के बारे में शिक्षित करने के लिए प्रतिब थीं। पिएरो मेदा, कालामार्का के एक किसान ने कहा, ''हम उपभोक्ताओं तक स्वस्थ आहार पहुंचाने के लिए घरेलू कामगारों की यूनियन के साथ मिलकर काम करते हैं। सित्राहो की सहभागिता केवल खाद्य पदार्थ प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे उपभोक्ता जागरुकता, और छोटे किसानों के लिए स्थानीय बाज़ार स्थापित करने में भी मदद करती है। इनके मायम से कृषि नीति के महत्वपूर्ण मुों पर किसानों के साथ राजनीतिक एकजुटता भी बनती है। उदाहरण के लिए, सित्राहो बोलिविया के उपभोक्ता संगठन का एक सक्रिय सदस्य है, जो कि कामगारों, कार्यकर्ताओं, और उपभोक्ता समूहों का एक व्यापक गठबांन है, जिसने हाल में एक घोषणापत्र जारी किया जिसमें सरकार द्वारा ट्रांसजेनिक फसलों और औद्योगिक कृषि को सहयोग देने की निंदा की गई।

भविष्य के लिए राह

सित्राहो का गरिमा और खाद्य संप्रभुता की खोज में घरेलू कामगार कार्यक्रम ग्रामीण पलायन के कारण हुई सामाजिक, आर्थिक, और पारिस्थितिकीय हानि को ठीक करने के सामूहिक प्रयासों का एक ठोस उदाहरण है। इस प्रकार के ग्रामीण–शहरी गठबांन, गिरती हुई कृषि अर्थव्यवस्थाओं के सहयोग और गांवों तथा शहरों में खाद्य संप्रभुता का निर्माण करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

शायद यूनियन के सामने आज तक की सबसे बड़ी चुनौती उसके सदस्यों के आघात का इतिहास रही है। कई घरेलू कामगार मानव तस्करी, बाल म, और उत्पीड़न का शिकार रहे हैं, ऐसे अनुभव जो अंदरूनी दमन के रूप में प्रकट होते हैं। हांलाकि बहुत से घरेलू कामगार अपनी ग्रामीण जड़ों से गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो अपने नियोक्ताओं के शहरी, उपभोक्तावादी मूल्यों को अपनाने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। उन्हें अक्सर रंगभेद का सामना करना पड़ा है और इसलिए सुपरमार्केट में देसी खानों को नकार कर आयातित खाद्य पदार्थ खरीदना उनके लिए स्तर और स्वीकार्यता स्थापित करने का तरीका बन जाता है।

अत:, खाद्य संप्रभुता के निर्माण के लिए रंगभेद, लिंगवाद और वर्गवाद को खत्म करने के अथक प्रयास; ग्रामीण पहचानों को पुनर्स्थापित करना; और कामगारों तथा किसानों, उत्पादकों और उपभोक्ताओं को जोड़ते हुए वर्ग–आधारित गठबांनों के निर्माण के मायम से सामूहिक संघर्ष स्थापित करने की आवश्यकता है। बोलिविया के घरेलू कामगारों से प्राप्त इस सीख को व्यापक स्तर पर, विश्व भर के प्रयासों में लागू किया जा सकता है, जिसके मायम से न्याय, सततता, स्वास्थ्य और संस्कृति पर आधारित सामुदायिक खाद्य प्रणालियां बनाई जा सकती हैं।

केरेन पोमियर और तान्या करसेन

केरेन पोमियर बोलिविया की कृषि विशेषज्ञ और कार्यकर्ता हैं जो सित्राहो के साथ गरिमा और खाद्य संप्रभुता की खोज में घरेलू कामगार कार्यक्रम के सहयोग में काम करती हैं।
ईमेल: karenpf@hotmail.es

तान्या करसेन इंस्टिट्यूट फॉर फूड ऐंड डेवलपमेन्ट पॉलिसी/ फूड फर्स्ट इन ओकलेंड, केलिफोर्निया, यू.एस.ए. में शोा समन्वयक हैं। (www.foodfirst.org).
ईमेल: tkerssen@foodfirst.org

पहली बार http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/global/rural-urban-linkages/domestic-workers-building-food-sovereignty पर प्रकाशित किया गया।
स्रोत: <https://www.radicalecologicaldemocracy.org/between-city-and-country-domestic-workers-building-food-sovereignty/>

पाठकों के लिए संदेश:

प्रिय पाठकों, यदि आप समुदाय व संरक्षण की प्रति किसी अलग पते पर प्राप्त करना चाहते है तो कृपया हमें अपना पता milindwani@yahoo.com पर या नीचे लिखे पते पर भेज दें।

कल्पवृक्ष

डॉक्यूमेन्टेशन ऐंड आउटरीच सेन्टर, अपार्टमेंट ५, श्री दत्ता कृपा, ९०८, डेक्कन जिमखाना,
पुणे ४११००४. महाराष्ट्र – भारत
वेबसाइट : www.kalpavriksh.org

समुदाय व संरक्षण : जैव विविधता संरक्षण तथा आजीविका सुरक्षा संस्करण अंक ९, नं. ४ जूलै २०१९ – दिसंबर २०१९

संकलन एवं संपादन : मिलिन्द वाणी

संपादकीय सहयोग : अनुराधा अर्जुनवाडकर

अनुवाद : निधि अग्रवाल

फोटो : आशिष कोठारी, खमीर, सित्राहो–एस.पी.

प्रकाशक :
कल्पवृक्ष,
अपार्टमेंट ५, श्री दत्ता कृपा, ९०८,
डेक्कन जिमखाना, पुणे–४११००४.
फोन : ९१–२०–२५६७५४५०,
फैक्स : ९१–२०–२५६५४२३९
ई–मेल : KVoutreach@gmail.com,
वेबसाइट : www.Kalpavriksh.org

आर्थिक सहयोग : मिजेरिओर, आचेव, जर्मनी

निजी वितरण के लिये

प्रकाशित विषयवस्तु (Printed matter)

सेवा में,